श्रीमती. सांता सिला देवी और अन्य

बनाम

धीरेंद्र नाथ सेन और अन्य

फैसले की तारीख: 26/04/1963

बेंच: बी.पी.सिन्हा, सीजे,जे.सी शाह और एन.राजागोपाला अयंगर

कार्य:मध्यस्थता-पंचाट की अपूर्णता-मध्यस्थता की चुप्पी निर्णय के लिए लगाई गई याचिका- इसका तात्पर्य याचिका की अस्वीकृति से है- पंचाट की वैधता-यदि उचित रूप से संभव हो तो बरकरार रखी जानी चाहिए - मध्यस्थ को विवाद के प्रत्येक मामले का निर्णय तब तक करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि विशेष रूप से आवश्यक ना हो- मध्यस्थता अधिनियम-1940

अपीलकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही हेमलता सैन के उत्तराधिकारी हैं, जिनकी मृत्यु बिना वसीयत किए 1929 में विचारणीय संपति को छोड़े बिना हो गई। उत्तराधिकारियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और उत्तराधिकारियों ने विभाजन के लिए एक समझौता किया था जिसमें हिस्सों का निर्धारण है। अन्य प्रावधानों के तहत जिसमें से अपील दूसरे अपील कर्ता को पांच आन्ना हिस्सा ग्लास फैक्ट्री में मिलना था और बाकी बचे

सदस्य ग्यारह आन्ना को विभाजित कर रहे थे। फिर विवाद उत्पन्न हुआ तथा पक्षकारों एक इकरारनामा निष्पादित किया कि मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का निस्तारण किया जाए। इससे पहले कि संदर्भ को मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता उत्तरदाता द्वारा उच्च न्यायालय में धारा 20 मध्यस्थता अधिनियम के तहत आवेदन किया कि समझौते को न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश देने वाले आदेश और मध्यस्थ को संदर्भ देने के लिए जो पक्षकारों द्वारा

2

नियुक्त है। वर्तमान अपीलार्थियाें को उत्तरदाताओ के रूप में पक्षकार बनाया गया। न्यायालय ने विवादों के संदर्भ के लिए करार में नामित मध्यस्थ को भेजने का आदेश पारित किया। मध्यस्थ ने इस संदर्भ में प्रवेश किया और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पंचाट पारित किया। पंचाट उस न्यायालय में दाखिल किया गया जिस न्यायालय में अपील कर्ता द्वारा इसे विभिन्न आधारों पर अपाश्त कराने के लिए आवेदन किया गया था जिनमें से प्रमुख यह था कि पंचाट अधुरा था, उसमें जो भी विवाद थे मध्यस्थता के लिए संदर्भ किया गया जिसका निपटारा नहीं किया गया था। जिस एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आवेदन आया था उन्होंने सुनवाई करते हुए आवेदन खारिज कर दिया और पंचाट में निर्धारित शर्तों के आधार पर डिक्री पारित करने का निर्देश दिया। अपीलार्थियों द्वारा उच्च

न्यायालय में दो अपील दायर की जिसमें एक आदेश पंचाट को अपाश्त करने से इंकार करने तथा दूसरा डिक्री की शर्तों से अलग पंचाट को खारिज कर दिया। वर्तमान अपील स्पेशल लीव के माध्यम से न्यायालय में दाखिल की गई। मुख्य तर्क यह उठाया गया है कि पंचाट अधूरा था क्योंकि पंचाट में तीन मुदे जो संदर्भ हेतु मध्यस्थ को भेजे गए थे उन पर खुलासा नहीं किया गया। जो इस प्रकार हैं (क) ग्लास वर्क लिमिटेड के खाते और लाभ के संबंध में पंचाट में काेई दिशा निर्देश नहीं दिए गए जो कि पंचाट को अवैध घोषित करता था। (ख) पंचाट मध्यस्थता करार में की गई प्रार्थना को पूर्ण करने में असफल रहा क्योंकि मध्यस्थ को ग्लास कंपनी को भविष्य के प्रबंधन में दिशा निर्देश दिए जाने थे। (ग) मध्यस्थता जिस पर साक्ष्य ली गई है यह आक्षेप था कि धन के दुर्पयोग के संबंध में छठा उत्तरदाता था लेकिन मध्यस्थ ने आवार्ड मे स्पष्ट नहीं किया कि आरोप बनता था कि नहीं और इस संबंध में किसी प्रकार के दिशा निर्देश मामले में नहीं दिए गए।

निर्णित किया कि न्यायालय को पंचाट की इच्छा के अनुरूप कार्य करना चाहिए यदि सम्भव हो तो ना कि उसे अवैध बताकर नष्ट कर देना चाहिए।

सैलबी बनाम व्हिटब्रेड एंड कम्पनी 1917 आई.के.बी. 736 का उल्लेख किया है -

जब तक कि मध्यस्थता के संदर्भ में विशेष रूप से इसकी आवश्यकता न हो मध्यस्थ प्रत्येक दावे के पृथक से निपटारे के लिए बाध्य नहीं है लेकिन वह एक समेकित पंचाट पारित कर सकता है।

रे ब्राउन और क्रॉयडन कैनाल कंपनी (1839) 9 एड और ई 11 522:112 ईआर 1309 और ज्वेल बनाम क्रिस्टे (1867) एलआरसीपी 296 का उल्लेख किया -

मध्यस्थ के समक्ष रखे गए विषय पर मध्यस्थ की चुप्पी का मतलब है कि मध्यस्थ ने ऐसी याचिका को अस्वीकृत कर दिया है। जब तक विपरीत प्रतीत न हो, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि पंचाट अनन्तः सभी मामलों का निपटारा करता है। जहां एक पंचाट को "डे प्रैमिसिस" बनाया जाता है, वहां अनुमान लगाया जाता है कि मध्यस्थ का इरादा अंततः सभी का निपटान करने का था और उसका ऐसा पंचाट अंतिम माना जाएगा। यदि किसी भी इरादे से ऐसा किया गया हो।

हैरिसन बनाम क्रिसविक, (1853) 138 ईआर 1284 का उल्लेख -

यद्यपि पंचाट स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है कि वह "डी प्रैमिसिस" बनाया गया तथा विवाद से संबंधित सभी मामलों को मध्यस्थ को भेजे गये थे, एक उपधारण है कि पंचाट पूर्ण है। पंचाट की चुप्पी दावे की गणना के संबंध में राहत के दावे को खारिज करने वाले निर्णय के रूप में

अभिप्रेत है। यदि तकनीकी कारणों से पट्टा रद्द कर दिया था यह आवश्यक नहीं है कि पट्टे की अवैधता को घोषित करता है। पट्टे की अमान्यता पर देय राशि का हिसाब किताब लेते हुए पट्टे के अन्य प्रावधान बनाने में समायोजित नहीं किया गया। इसलिए तर्क यह है कि दावे की प्रकृति के लिए विशेष न्याय निर्णय की आवश्यकता को निरस्त किया जाता है।

पंचाट के प्रश्न पर मध्यस्थ की चुप्पी पर मामले के तथ्य और परिस्थितियों में ग्लास कम्पनी के भविष्य के प्रबंधन व उसकी असफलता के बारे में प्रबंधन के संबंध में कोई विशेष प्रावधान करे इसलिए अधिकारों के संबंध में कोई कमी ना छोड़े, यह माना जाना चाहिए कि होने वाले पक्षों का अधिकार छोड़ दिया गया है तथा यह सामान्य कानून के द्वारा निर्धारित किया जाता है।

4

दावे के संबंध में किसी प्रावधान का अभाव। अपीलकर्ताओ को इस आधार पर कि वह पैसे का दुरूपयोग करने में सक्षम है कि केवल एक ही व्याख्या और वह यह कि मध्यस्थ के द्वारा दावों को अस्वीकार कर दिया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 197/1961

उच्च न्यायालय कलकत्ता द्वारा मूल आदेश संख्या 122 और 156/1956 की अपील में पारित आदेश और डिक्री दिनांकित 29 जनवरी,

1957 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

जीएस पाठक, ए एन सिन्हा और पी के मुखर्जी ..... अपीलकर्ताओ की ओर से

ए वी विस्मनाथ शास्त्री, बी आर एल लयंगर और एस एन मुखर्जी ....उत्तरदाताओ की ओर से

1963. 26 अप्रैल को न्यायालय का फैसला अय्यंगार जे. के द्वारा दिया गया -

यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति के द्वारा पेश की गई अपील है, जिसमें एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की गई थी जिसमें पंचाट दिनांक 27.05.1955 को अपास्त करने से इन्कार कर दिया गया था।

दूसरे अपीलकर्ता के पिता हेमेन्द्र नाथ सेन की 1929 में बिना वसीयत बनाए मृत्यु हो गई जिससे उसकी विधवा प्रेम तरंगीनी देवी और उसके 8 बच्चे है।उत्तरदाता 1,2,3,4,व 7 दूसरे अपीलार्थी के भाई हैं। पांचवी उत्तरदाता एक मृत भाई की विधवा है जिसकी मृत्यु 1933 में हुई थी जबकि 8 वें उत्तरदाता दूसरे उत्तरदाता की पत्नी है। पहली अपीलकर्ता दूसरे अपीलकर्ता की पत्नी है। पक्षकारान हिन्दू विधि के सिद्धांत दयाभागा स्कूल ऑफ हिन्दू विधि द्वारा शासित थे। हेमेंद्र नाथ ने काफी संपत्ति छोड़ी और उनकी मृत्यु पर उनके कई

उत्तराधिकारियों के बीच विवाद पैदा हो गया, लेकिन 31 जनवरी, 1933 को एक समझौते के तहत इनका निपटारा कर दिया गया। तब तक पांचवे उत्तरदाता के पति के एक बेटे की मृत्यु हो गई थी और एक विधवा (पांचवा उत्तरदाता) और इसके बाद विधवा, 7 बेटों और विधवा बहू ने इस समझौते में प्रवेश किया जिसके द्वारा मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को उनके बीच विभाजित किया गया था। मोटे तौर पर समझौते में 9 पक्षों के हिस्से को 1/9 के हिसाब से निर्दिष्ट किया गया था, हालाँकि, दोनों विधवाओं को उनके भरण-पोषण के लिए उनके जीवन भर का हिस्सा आवंटित किया गया। यह भी प्रावधान था कि एक ग्लास फैक्ट्री के संबंध में दूसरे अपीलकर्ता को 5 आने का हिस्सा देना था, शेष सदस्यों को ग्यारह आने को विभाजित करना था (संभवतः क्योंकि पहले अपीलकर्ता का पैसा शुरुआती पूंजी के लिए चला गया था) कुछ निर्दिष्ट आकस्मिकताओं के घटित होने तक। हालाँकि, पार्टियों के बीच ताजा विवाद उत्पन्न हुए और 11 मई, 1953 को एक औपचारिक समझौते के द्वारा, उन्होंने उन विवादों को आपस में सुलझा लिया और इसे कलकत्ता के एक विद्वान वकील और न्यायविद् डॉ. राधा बिनोद पाल की एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने पर सहमत हुए। चूंकि संदर्भ की शर्तों की अपील में हमारे समक्ष आग्रह किए गए बिंदुओं से कुछ प्रासंगिकता है, इसलिए उन्हें निर्धारित करना सुविधाजनक होगा।

"हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, इस बात से सहमत हैं कि सबसे पहले न्यू इंडियन ग्लास वर्क्स लिमिटेड से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में सभी विवादों का उल्लेख करें, जिसमें उसके प्रबंधन और उसके संबंध में किसी भी पक्ष के, उक्त कंपनी के लिए या उससे उत्पन्न होने वाले कृत्य शामिल हैं, और उसके भविष्य के प्रबंधन के लिए आर एन सेन (सातवें उत्तरदाता) के पक्ष में कथित और ए एन सेन (दूसरे अपीलकर्ता) के पक्ष में पूर्व पट्टे से कथित संबंधित विवाद शामिल है और एफ एन सेन (छठा उत्तरदाता) के पक्ष में उक्त कंपनी के व्यवसाय, उसकी वैधता और वैधानिकता से कथित विवाद शामिल हैं और एकमात्र-मध्यस्थता के लिए डॉ. राधा

6

बिनोदे - पाल, अधिवक्ता को यहां लिखित या अन्यथा अनुसूची के अनुसार संयुक्त संपत्तियों के संबंध में सभी विवाद, जो पार्टियों या उनमें से कुछ के स्वामित्व में थे या हैं, से संबंधित विवाद शामिल हैं। उक्त मध्यस्थ को उक्त संयुक्त संपत्तियों की जांच, पता लगाना और विभाजन करना है। हम सहमत हैं कि डॉ. राधा बिनोदे पाल के पास सारांश शक्तियां होंगी और उनके द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा, वह अंतिम और निर्णायक होगा तथा पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।"

इसके बाद एक अनुसूची बनाई गई जिसमें संयुक्त संपत्तियों को

निर्दिष्ट किया गया और इस दस्तावेज़ पर परिवार के सभी सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए।

हालाँकि, संदर्भ मध्यस्थ को प्रस्तुत किए जाने से पहले, उत्तरदाताओं ने 12 जुलाई, 1954 को धारा 20 भारतीय मध्यस्थता अधिनियम 1940 के तहत इसके मूल पक्ष पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया था। जिसमें समझौते को न्यायालय में दायर करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए और पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ काे संदर्भ के लिए आदेश हेतु। उन अपीलकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए जिन्हें उस आवेदन के उत्तरदाता के रूप में शामिल किया गया था और सुनवाई के बाद, 29 नवंबर, 1954 को एक आदेश दिया गया था जिसमें समझौते में निर्धारित विवादों को उसमें नामित मध्यस्थ के पास भेजा गया था। मध्यस्थ ने 16 जनवरी, 1955 को संदर्भ में प्रवेश किया और उसके बाद पार्टियों ने अपने संबंधित दावों और तर्कों को निर्धारित करते हुए उनके समक्ष मामलों के बयान दायर किए। साक्ष्य लिया गया और वकील को सुना गया और उसके बाद मध्यस्थ ने 27 मई, 1955 को अपना फैसला सुनाया। यह इस फैसले की वैधता है जो इन कार्यवाहियों में चुनौती के अधीन है। हम, केवल आधार स्पष्ट करने के लिए, इस स्तर पर भी उल्लेख कर सकते हैं कि मध्यस्थ के खिलाफ कोई 'कदाचार' का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन मुख्य आधार जिस पर निर्णय को चुनौती दी गई है वह यह है कि यह अधूरा है।

यह पंचाट एक लंबा दस्तावेज़ है और इसका उद्देश्य उन सभी विवादों का निर्णय करना है जो उन्हें संदर्भित किए गए थे। यह किसी विशिष्ट मामले या यहां तक कि दर्ज किए गए विशेष निर्णयों के कारणों के संबंध में पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों या यहां तक कि तर्कों के कारण को भी निर्धारित नहीं करता है, बल्कि सुविधा के लिए इसे एक वाद में एक डिक्री कहा जा सकता है।यह पंचाट 29 जून, 1955 को न्यायालय में दायर किया गया था, और उसके बाद अपीलकर्ताओं ने विभिन्न आधारों पर इसे अपास्त करने के लिए एक आवेदन किया था, जिसमें सभी विवाद शामिल थे। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया था जिसमें मुख्य बात यह थी कि यह पंचाट अधूरा था, मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था, इसका निपटारा नहीं किया गया था। आवेदन मूल एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आया और इसे 26 मई, 1956 को खारिज कर दिया गया, विद्वान न्यायाधीश ने पंचाट के संदर्भ में एक डिक्री पारित करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं ने दो अपीलें कीं, एक फैसले को रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ और दूसरी उसके संदर्भ में डिक्री के खिलाफ। इन्हें 29 जनवरी, 1957 के फैसले द्वारा सुना और निपटाया गया, जिसमें अपीलों को खारिज करने का निर्देश दिया गया और उसके बाद उन्होंने आवेदन किया और इस अदालत से विशेष अनुमति प्राप्त की और उसके अनुसरण में वर्तमान अपील जो कि हाई कोर्ट द्वारा दो अपील दायर किए

गए फैसले के खिलाफ एक समेकित अपील है।

उच्च न्यायालय के समक्ष पंचाट की वैधता या वैधानिकता पर बहुत बड़ी संख्या में आपत्तियां उठाई गईं और उन पर प्रथम दृष्टया न्यायाधीश और अपीलीय पीठ द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया और निपटाया गया। हालाँकि, इनमें से अधिकांश को हमारे सामने दोहराया नहीं गया था और अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री पाठक ने सूचित किया था कि वह केवल तीन आधारों पर अभिकथित करेंगे : (1) कि सभी विवाद जो मध्यस्थ को भेजे गए थे, उनका निपटारा नहीं किया गया है। पंचाट द्वारा, और इस कारण से पंचाट अधूरा था और पंचाट रद्द करना पड़ा। उन्होंने कहा कि तीन मामलों के संबंध में यह अपूर्णता थी: (क) पंचाट ने ग्लास वर्क्स

8

लिमिटेड के पट्टे के संदर्भ में खातों और मुनाफे के प्रतिपादन के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया था, जिसे पंचाट को अमान्य घोषित किया था और कंपनी पर बाध्यकारी नहीं था जिसमें सभी शेयरों पर पक्षकारों का स्वामित्व था, (ख) पक्षकारों ने अपने संदर्भ समझौते में मध्यस्थ से विशेष रूप से अपेक्षा की थी कि उसे ग्लास कंपनी के भविष्य के प्रबंधन के संबंध में निर्देश देना चाहिए, लेकिन पंचाट इस अनुरोध का पालन करने में असफल रहा।, (ग) वहां संदर्भ में एक आरोप लगाया गया था, और छठे

प्रतिवादी द्वारा धन के दुरुपयोग के संबंध में मध्यस्थ के समक्ष कौन से साक्ष्य पेश किए गए थे। मध्यस्थ ने अपने फैसले में यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि हेराफेरी का यह आरोप लगाया गया था या नहीं, न ही उसने मामले के संबंध में कोई निर्देश दिया गया। शयह पंचाट की अपूर्णता को छूने वाली आपत्तियों के प्रमुख से संबंधित थे। (2) दूसरा आग्रह यह था: इस पंचाट में निर्देश दिया गया था कि बर्दवान जिले के केतुग्राम में स्थित भूमि का एक टुकड़ा पंचाट व अन्य न्यायालय में दाखिल करने की लागत और शुल्क को पूरा करने के लिए बिक्री के लिए सातवें उत्तराधिकारी को आवंटित किया जाए। उसके संदर्भ में कार्यवाही और उक्त लागतों और शुल्कों को पूरा करने के बाद शेष शेष राशि को अपने और छः अन्य नामित लोगों के बीच समान रूप से वितरित करना। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि विवाद में संपत्ति का यह विश्वास बनाना मध्यस्थ की शक्ति से परे था। (3) संपत्ति की कई वस्तुओं के मूल्य पंचाट में निर्दिष्ट किए गए थे और विभाजन इस मूल्यांकन के आधार पर किया गया था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि मध्यस्थ स्वयं संपत्तियों का मूल्यांकन न करके अपने कर्तव्य में विफल रहा, लेकिन उसने एक या अन्य पक्षों द्वारा सुझाए गए मूल्यों को अपनाया था।

इन बिंदुओं से निपटेंगे। हालाँकि, हम मानते हैं कि पंचाट की अपूर्णता के बारे में उपरोक्त बिंदुओं में से केवल पहला बिंदु ही विचार करने योग्य है और अन्य दो में वास्तव में कोई सार नहीं है और पहले दूसरे

और तीसरे का निपटान करना सुविधाजनक होगा। उपरोक्त बिंदु.

9

पंचाट द्वारा बनाया गया विश्वास जिस बिंदु संख्या 2 से संबंधित है वह निम्नलिखित शब्दों में है। पंचाट का खंड 13 जिस पर संबंधित खंड चलता है:

> "बर्दवान जिले के केतुग्राम, कटवा में भूमि श्री धीरेंद्र नाथ सेन को ट्रस्ट में आवंटित की गई है, ताकि मध्यस्थता कार्यवाही के मिनटों, बयानों और दस्तावेजों के साथ-साथ पंचाट दाखिल करने की लागत और शुल्क को पूरा करने के लिए इसे बेचा जा सके। पंचाट के साथ अदालत में दायर किया जाए और उक्त लागत और शुल्क को पूरा करने के बाद शेष राशि, यदि कोई हो, को अपने और छः अन्य बेटों के बीच समान रूप से वितरित किया जाए..."

और फिर पंचाट बिक्री आय के अपर्याप्त होने की आकस्मिकता के लिए प्रावधान करने के लिए आगे बढ़ता है। विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि मध्यस्थ के पास संपत्ति के संबंध में ट्रस्ट बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिसे पार्टियों के बीच विभाजित करने के लिए उसे बुलाया गया था। हालाँकि, यह विवाद मध्यस्थ ने जो किया था उसकी

गलत व्याख्या पर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने कथित तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने केवल पंचाट दाखिल करने में होने वाली लागत के भुगतान का प्रावधान किया है, जो स्पष्ट रूप से, यदि यह एक वैध पंचाट होता, तो उन सभी पक्षों को वहन करना होगा जिनकी संपत्ति पंचाट के तहत विभाजित की जा रही थी और उन्होंने प्रावधान किया था केवल इसी उद्देश्य के लिए और संपत्ति के हकदार पक्षों के बीच अधिशेष बिक्री आय का विभाजन करने का निर्देश दिया था। जब मामले के इस पहलू को विद्वान वकील को बताया गया तो विवाद को गंभीरता से नहीं रखा गया।

मध्यस्थ द्वारा स्वयं संपत्ति का मूल्य निर्धारित नहीं करने के बिंदु में उस बिंदु से भी कम योग्यता है जिसे हमने अब निपटाया है। मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के मिनट्स अदालत के सामने पेश किए गए थे और उनमें

10

स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि वस्तुओं के अनुमानित मूल्य, जैसा कि पंचाट में निर्धारित किया गया था, वे थे जिन पर पार्टियों ने स्वयं सहमति व्यक्त की थी। इसलिए, इस मुद्दे पर आगे किसी विचार की आवश्यकता नहीं है।

पंचाट की अपूर्णता के संबंध में हम सबसे पहले ग्लास फैक्ट्री के पट्टे के संबंध में मुनाफे का हिसाब देने के निर्देश के अभाव पर आधारित विवाद से निपटेंगे, जिसे शून्य घोषित कर दिया गया था। इस आपत्ति से

संबंधित प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं- मध्यस्थता समझौते के तहत संदर्भित विवादों का पहला प्रमुख यह था "- न्यू इंडियन ग्लास वर्क्स लिमिटेड के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले विवाद, जिसमें उसके प्रबंधन और उसके संबंध में किसी भी पक्ष के कार्य शामिल हैं या उक्त कंपनी के संबंध में या उससे उत्पन्न होने के संबंध में"। प्रथम अपीलकर्ता द्वारा 12 फरवरी, 1955 को मध्यस्थ के समक्ष दायर एक बयान में इसे प्रवर्धित किया था।

> "पैरा 12. धीरेंद्र नाथ सेन, फणींद्र नाथ सेन, सत्येन्द्र नाथ सेन, रवीन्द्र नाथ सेन और जीतेन्द्र नाथ सेन को उक्त कंपनी (न्यू इंडियन ग्लास वर्क्स) की संपत्तियों और/या संपत्तियों के साथ अपने लेन-देन का सच्चा विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और लेखांकन पर देय राशि में से मेरे हिस्से के लिए एक पंचाट पारित किया जाए।
>
> 13. रवीन्द्र नाथ सेन और फणीन्द्र नाथ सेन के पक्ष में कथित पट्टे मुझे धोखा देने के लिए धोखाधड़ी से बनाये गये थे। मैं एक निर्णय के लिए दावा करता हूं कि उक्त पट्टे शून्य हैं और मैं कथित पट्टेदारों के खिलाफ खातों और लेखांकन पर मुनाफे के मेरे हिस्से के पंचाट के लिए प्रार्थना करता हूं।"

मध्यस्थ ने फैसले के पैराग्राफ 9 (सी) में निर्णय लिया कि "रवींद्र नाथ सेन के पक्ष में फैक्ट्री का कथित पट्टा शून्य घोषित किया गया और इसका कंपनी या शेयरधारकों पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा।" हालाँकि, पंचाट में इस पट्टे को शून्य घोषित करने के संबंध में रवीन्द्र नाथ सेन को मुनाफे का हिसाब देने का आदेश देने या इनकार करने का कोई और निर्देश नहीं था। अब जिस मुद्दे पर आग्रह किया गया है वह यह है कि पंचाट अधूरा है,

11

इसमें लेखांकन के लिए परिणामी आदेश देकर या लेखांकन के लिए अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज करके और उनके हिस्से के लिए पट्टे की इस घोषणा या अमान्यता का पालन नहीं किया गया है। ऐसे खातों को लेने पर देय राशियाँ पाई गईं। मूल पक्ष के साथ-साथ अपीलीय पीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश ने हैरिसन बनाम क्रिसविक में एक अंग्रेजी निर्णय के अधिकार पर इस आपत्ति को खारिज कर दिया, जहां पार्के, बी ने अदालत का फैसला सुनाते हुए कहा :

> "अपने सामने रखे गए विषय पर मध्यस्थ की चुप्पी का मतलब है कि मध्यस्थ ने ऐसी याचिका को अस्वीकार कर दिया है।"

श्री पाठक द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि इस निर्णय को उच्च

न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा गलत समझा गया था, और वास्तव में, यह उनके पक्ष में एक अधिकार था। पंचाट को रद्द करने के आधार के रूप में सामान्य दलीलों के न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ने मध्यस्थ के समक्ष एक क्रॉस-दावा पेश किया था और मध्यस्थ ने परिवादी के क्रॉस दावे को अनुमति या नकारात्मक किए बिना वादी को विशेष रूप से एक निश्चित राशि के लिए डिक्री प्रदान की थी। इस आपत्ति से निपटते हुए कोर्ट की ओर से बोलने वाले पार्के, बी ने कहा:

"एकमात्र सवाल यह है कि क्या मध्यस्थ ने अपने फैसले से, यदि स्पष्ट शब्दों में नहीं तो, अंततः मामले का निपटारा कर दिया है। नियम जैसा कि बिक्र्स बनाम ट्रिप्पेट के नोट्स में दिया गया है, वह है, जहां एक फैसला होने का दावा करता है मेड डे प्रैमिसिस 'यहां तक कि जहां सामान्य रिहाई का कोई पंचाट नहीं है, वहां प्रस्तुत किए गए और मध्यस्थ के समक्ष लाए गए कुछ मामलों के बारे में फैसले की चुप्पी, इसे उसके द्वारा निहित अधिकार का पर्याप्त अभ्यास होने से नहीं रोकती है। एक पंचाट अच्छा है, भले ही मध्यस्थ ने उसे सौंपे गए कई

12

अलग-अलग मामलों में से प्रत्येक या किसी पर कोई अलग निर्णय नहीं दिया है, बशर्ते ऐसा प्रतीत न हो कि उसने किसी को बाहर रखा है... .. जहां एक पंचाट को डी प्रैमिसिस बनाया गया है, वहां यह अनुमान

लगाया जाता है कि मध्यस्थ का इरादा अंततः सभी मामलों के अन्तर को निपटान करने है और उसका पंचाट अंतिम माना जाएगा, यदि किसी इरादे से ऐसा किया जा सके। नियम यह है कि जहां वादी द्वारा कोई और दावा किया गया है, या प्रतिवादी द्वारा कोई क्रॉस डिमांड की गई है, और पंचाट, संदर्भित मामलों से संबंधित होने का दावा करते हुए, ऐसे दावे या क्रॉस डिमांड का सम्मान करते हुए चुप है, पंचाट एक निर्णय के समान है कि वादी के पास ऐसा कोई और दावा है, या कि प्रतिवादी की क्रॉस मांग अस्थिर है: लेकिन जहां मामले को उसकी प्रकृति से निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, केवल चुप्पी से काम नहीं चलेगा।

श्री पाठक इस तर्क के समर्थन में भरोसा करते हैं कि अब हमारे सामने आए मामले में मध्यस्थ को लेखांकन के दावे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और अस्वीकृति के लिए स्पष्ट शब्दों में निर्णय देने की आवश्यकता थी और उस दावे की विफलता को केवल मध्यस्थ द्वारा इससे निपटने में विफलता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। विद्वान वकील ने बताया कि क्रॉस डिमांड या क्रॉस क्लेम का मामला, जिसके साथ पार्के, बी निपट रहे थे वह एक स्वतंत्र दावे से काफी अलग था, जैसे कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए लेखांकन के लिए, जहां वादी के लिए एक राशि का फैसला किया गया है, इसमें आवश्यक रूप से प्रतिवादी द्वारा किए गए क्रॉस दावे की स्वीकृति या अस्वीकृति शामिल है, लेकिन

जहां स्थिति अलग है वहां दावा स्वतंत्र आधार पर चलने योग्य है।

इस बिंदु पर विचार करने से पहले कुछ बुनियादी स्थितियों पर जोर देना आवश्यक है। उनमें से पहला यह है कि एक न्यायालय को किसी पंचाट का समर्थन करने की इच्छा के साथ संपर्क करना चाहिए, यदि यह उचित रूप से संभव है, न कि इसे अवैध कहकर इसे नष्ट कर देना चाहिए (सैल्बी बनाम व्हिटब्रेड एंड कंपनी,।

13

इसके अलावा यह स्पष्ट है कि जब तक मध्यस्थता के संदर्भ में विशेष रूप से आवश्यक न हो, मध्यस्थ प्रत्येक दावें या मामला को अलग से निपटने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक समेकित पंचाट दे सकता है। कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि जब तक विशेष रूप से आवश्यक न हो, किसी पंचाट को मतभेद के प्रत्येक मामले पर मध्यस्थ के निर्णय को औपचारिक रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। (रे. ब्राउन और द क्रॉयडन कैनाल कंपनी (1839) 9 विज्ञापन। और एल. 522-112 ईआर 1309. और ज्वेल बनाम क्रिस्टी (1867], एलआर 2 सीपी 296 । इसके अलावा, पार्के के रूप में, बी. ने खुद इसे हैरिसन बनाम क्रिसविक [1853] 138 ईआर 1254।) में बहस के दौरान रखा था:

"जब तक कोई विपरीत बात सामने न आए, अदालत यह मान लेगी कि पंचाट अंततः मतभेद के सभी

मामलों का निपटारा कर देता है।"

और पहले उद्धृत उद्धरण से एक वाक्य दोहराने के लिए:

> "जहां एक पंचाट डे प्रैमिसिस दिया जाता है, वहां यह माना जाता है कि मध्यस्थ का इरादा अंतर के सभी मामलों को अंतिम रूप से निपटाने का है; और उसका पंचाट अंतिम माना जाएगा, यदि किसी इरादे से ऐसा किया जा सकता है।"

हम इन विचारों के आलोक में हमें संबोधित तर्क पर विचार करेंगे। अब पंचाट एक पैराग्राफ के साथ खुलता है, जिसमें संदर्भ निर्धारित करने के बाद कहा गया है:

> "हालांकि मैंने सभी आरोपों को सुना है और उन पर विधिवत विचार किया है, पार्टियों के संबंधित मामलों के संबंध में मेरे सामने सबूत पेश किए गए हैं..... मैं इसे लिखित रूप में अपना पंचाट देता हूं और

14

> प्रकाशित करता हूं ऊपर उल्लिखित सभी विवादों के संदर्भ में।"

इसे शायद ही जोड़ने की आवश्यकता है कि मध्यस्थता समझौता और दायर किए गए बयान, जिनके उद्धरण हमने पहले दिए हैं, इस पंचाट

के साथ शामिल दस्तावेजों में से थे और मध्यस्थ द्वारा विचार किए गए मामलों में शामिल थे।

वे इस पंचाट के माध्यम से विवादों को सुलझाने का इरादा रखते थे। इसलिए, इस पंचाट का उद्देश्य और कथित रूप से इस निर्णय के लिए उठाए गए सभी विवादों का फैसला करना है और इसलिए न्यायालय यह मान लेगा कि उसने किए गए प्रत्येक दावे या बचाव पक्ष पर विचार किया है और उसका निपटारा किया है। चूँकि अब निर्णय पर आपत्ति जताई गई है या स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसे "डी प्रूमिसिस" बनाया गया है, अर्थात, और मध्यस्थ को विवाद से संबंधित सभी मामलों को संदर्भित किया गया, एक धारणा है कि निर्णय पूरा हो गया है। इन परिस्थितियों में पार्के, बी द्वारा प्रतिपादित निर्माण का सिद्धांत मामले को उपयुक्त रूप से कवर करता है और लेखांकन के दावे के संबंध में पंचाट की चुप्पी को उस राहत के दावे को खारिज करने वाले निर्णय के रूप में लिया जाना चाहिए।

हम आगे इस सबमिशन की ओर जायेंगे कि यहां किए गए दावे की प्रकृति के लिए एक विशिष्ट निर्णय की आवश्यकता है और अपीलकर्ता तार्किक रूप से लेखांकन की राहत के हकदार थे, जब एक बार कारखाने के पट्टे को शून्य घोषित कर दिया गया था और उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंचाट कि गई घोषणा के कानूनी परिणाम से स्पष्ट रूप से निपटने में असमर्थ होने के कारण इसे अपूर्ण माना जाता है। हम इस विवाद को दो

कारणों से उचित नहीं मानते हैं: (1) यदि तकनीकी अनौपचारिकता के कारण पट्टे को शून्य माना जाता है, तो इसमें आवश्यक रूप से किसी भी लेखांकन को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लेखांकन अभिधारणाओं

15

के अनुसार, पट्टा अनुचित रूप से कम किराये के लिए होता है। यदि पट्टे को ऐसे किसी कारण से रद्द कर दिया जाता है, तो यह जरूरी नहीं होगा कि लेखांकन की राहत पट्टे की अमान्यता की घोषणा में निहित थी, (2) गैर स्थिर, लेखांकन लेने पर देय राशि नहीं दी गई है पंचाट के अन्य प्रावधान बनाने में ध्यान में रखा गया या समायोजित किया गया। इसलिए, इस आपत्ति को निरस्त किया जाना चाहिए।

पंचाट की अपूर्णता के संबंध में कहा गया है कि न्यू इंडियन ग्लास वर्क्स लिमिटेड के भविष्य के प्रबंधन के लिए मध्यस्थ अपने दवारा दिये गये अपने पंचाट में प्रदान करने में विफल रहा है। हम मानते हैं कि इस आपत्ति में भी कोई तथ्य नहीं है। पंचाट ने ग्लास कंपनी में पार्टियों के शेयरों की घोषणा की थी और उपधारा 9 (बी) ने कंपनी के मामलों के प्रबंधन के संबंध में किए गए समझौतों या व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया था, जिनकी वैधता और स्वामित्व संबंधी विवाद उठाए गए थे। जब उन कथित समझौतों को रद्द कर दिया गया और पार्टियों पर बाध्यकारी नहीं

होने की घोषणा की गई, तो कानून कदम उठाएगा और कंपनी के व्यवसाय और मामलों के प्रबंधन के संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, और मध्यस्थ हो सकता है कि मध्यस्थ ने उसने अच्छी तरह से विचार किया हो कि देश के कानून में निहित प्रावधान शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। इस संबंध में मध्यस्थ की चुप्पी और प्रबंधन के संबंध में कोई विशेष प्रावधान करने में उनकी विफलता ने पार्टियों के प्रबंधन के अधिकारों के संबंध में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इसे पार्टियों के अधिकार को छोड़ दिया जाना चाहिए। कंपनी के प्रबंधन पर लागू प्रासंगिक सामान्य कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि मध्यस्थ यह मानता है कि ये प्रावधान पार्टियों के अधिकारों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित करते हैं और यह नहीं मानते हैं कि इस मामले के संबंध में किसी विशेष प्रावधान की आवश्यकता है तो पंचाट उस बिंदु पर चुप रहेगा और यही मामलों की स्थिति के लिए स्पष्टीकरण हो सकता है।

आग्रह किया गया मध्यस्थ ने अपने पंचाट ने उत्तरदाताओं या उनमें से कुछ को इस आधार पर राहत

16

देने के लिए अपीलकर्ताओं के दावे का उल्लेख या निर्णय नहीं किया था कि उन्होंने कंपनी के धन का दुरुपयोग किया था और इसलिए, वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे। पार्टियों के बीच बंटवारे के लिए पैसा वापस गर्म

हो गया। इस दावे के संबंध में किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति केवल एक ही व्याख्या करने में सक्षम है और वह यह है कि मध्यस्थ ने दावे को खारिज कर दिया है। इसलिए, यह एक ऐसा उदाहरण है जहां पंचाट की चुप्पी एक स्पष्ट संकेत है, कथित तौर पर निर्णय पूर्ण होने और डी प्रैमिसिस को ध्यान में रखते हुए , उस संबंध में दावा बरकरार नहीं रखा गया था। इससे पंचाट अधूरा नहीं रहेगा। इसलिए हम मानते हैं कि अपूर्णता के आधार पर पंचाट की वैधता को चुनौती देने के लिए आग्रह किए गए तीन बिंदुओं में से किसी में भी कोई दम नहीं ।

अपील विफल हो जाती है और जुर्मान के साथ ख़ारिज किया जाता है ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक रीतिका चौहान**(न्यायिक अधिकारी)**द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः-यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।